State Government for his participation in the struggle for freedom (proof to be furnished)

(xi) either of his/her parents is transferred to a place where no Kendriya Vidyalaya exists; or

(xii) he or she is a child who is winner of National bravery awards of the national or state level; or

(xiii) he or she is a child of a teacher who has won National/President's Award; or

(xiv) he or she has shown special ability in sports or fine arts.

Representation relating to Kendriya Vidya Peedhom, Puranattukara

2690. SHRI O. RAJAGOPAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation regarding the delay in the promotion of the teaching staff of Kendriya Vidya Peedhom Puranattukara, Trichur, district of Kerala; and

(b) if so, what action has been taken in this regard?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) and (b) Yes Sir, A representation for granting promotion to the Junior Lecturers of Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, Puranattukara, Trichur Distt., to the post of Lecturer has been received. The Recruitment Rules for the post of Lecturer, however, do not provide for such promotion.

गैर-सरकारी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम

2691. **श्री बरजिन्दर सिंहः**
श्रीमती शबाना आज़मीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी स्कूलों में 10वीं तथा 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम अनेक वर्षों से निजी क्षेत्र में चल रहे स्कूलों की तुलना में निराशाजनक रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना बनाई है, यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पिछले वर्षों के परिणामों के आंकड़ों से पता चलता है कि निजी स्कूलों का पास प्रतिशत विशेषकर दिल्ली में राज्य द्वारा संचालित स्कूलों के पास प्रतिशत से निश्चित रूप से अधिक है। तथापि पास प्रतिशत में वृद्धि तथा गिरावट हमेशा आंशिक होती है। पिछले चार वर्षों के दौरान, सरकारी स्कूलों में कक्षा-X के परिणामों में 35.5% से 31.8% तथा कक्षा-XII के परिणामों में 68.76% से 62.9% का अन्तर आया है। जहां तक निजी स्कूलों का सम्बन्ध है, कक्षा X तथा XII दोनों के परिणामों में 83% से 88% का अन्तर आया है।

(ख) शिक्षा के समवर्ती सूची में होने के कारण विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थिति में सुधार लाने के लिए समय-समय पर आवश्यक कदम/उचित उपाय किए गए हैं।

(ग) सरकार ने स्कूलों विशेषकर सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई योजनाएं तैयार की हैं। इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, जिला शिक्षक शिक्षा संस्थानों के सामूहिक कार्यतंत्र द्वारा शिक्षकों का सेवा में तथा सेवा-पूर्व प्रशिक्षण सम्मिलित है। केन्द्र सरकार शैक्षिक प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं गणित शिक्षा में सुधार, कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम (क्लॉस) आदि जैसी केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से भी सहायता प्रदान करती है।

सभी स्तरों पर शिक्षा के विषय-सूची तथा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए भी अनेक उपाय किए गए हैं। इसमें पाठ्यक्रम का नवीनीकरण, पाठ्य-पुस्तकों में सुधार इत्यादि सम्मिलित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् जो स्कूल शिक्षा में शीर्ष निकाय है तथा भुवनेश्वर, भोपाल, अजमेर, मैसूर में स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों ने सभी स्तरों पर स्कूल शिक्षा में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।